

महत्त्वपूर्ण खनजिं को सुरक्षिति करने की राह पर भारत

यह एडिटोरियल 27/07/2024 को 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित "A push for critical minerals" लेख पर आधारित है। इसमें बजट 2024 में लायिम जैसे महत्त्वपूर्ण खनजिं पर सीमा शुल्क में छूट देने के भारत के रणनीतिक कदम की चर्चा की गई है, जो इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी और सतत ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह प्रयावरण लक्ष्यों और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबिद्धता को बढ़ाते हुए आयात नियन्त्रण को कम करने और घरेलू उत्पादन का समर्थन करने के देश के प्रयासों को रेखांकित करता है।

प्रलिमिस के लिये:

केंद्रीय बजट 2024-25, महत्त्वपूर्ण खनजि, लायिम, इलेक्ट्रिक वाहन, खान मंत्रालय, दुर्जलभ मूदा तत्त्व, गणनयान, खनजि सुरक्षा साइंडेन्सी, जम्मू और कश्मीर में लायिम भंडार, खनजि विदेश इंडिया लिमिटेड।

मेन्स के लिये:

भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनजिं का महत्त्व, भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनजिं से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

केंद्रीय बजट 2024-25 में ऊर्जा सुरक्षा को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में चहिनति किया गया है, जहाँ लायिम सहति विभिन्न **महत्त्वपूर्ण खनजिं** के लिये लायिम सीमा शुल्क छूट का प्रस्ताव किया गया है। यह रणनीतिक कदम इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी की ओर भारत के संक्रमण को तेज़ करने और अपनी शून्य-उत्तराधिकारी महत्त्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबिद्धता को रेखांकित करता है। चैंकिं **लायिम-आयन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs)** के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण और लागत-गहन घटक बनी हुई है, इसलिये इस छूट का उद्देश्य संसाधन एवं उत्पादन लागत को कम करना, विनियोग को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी समाधानों में नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

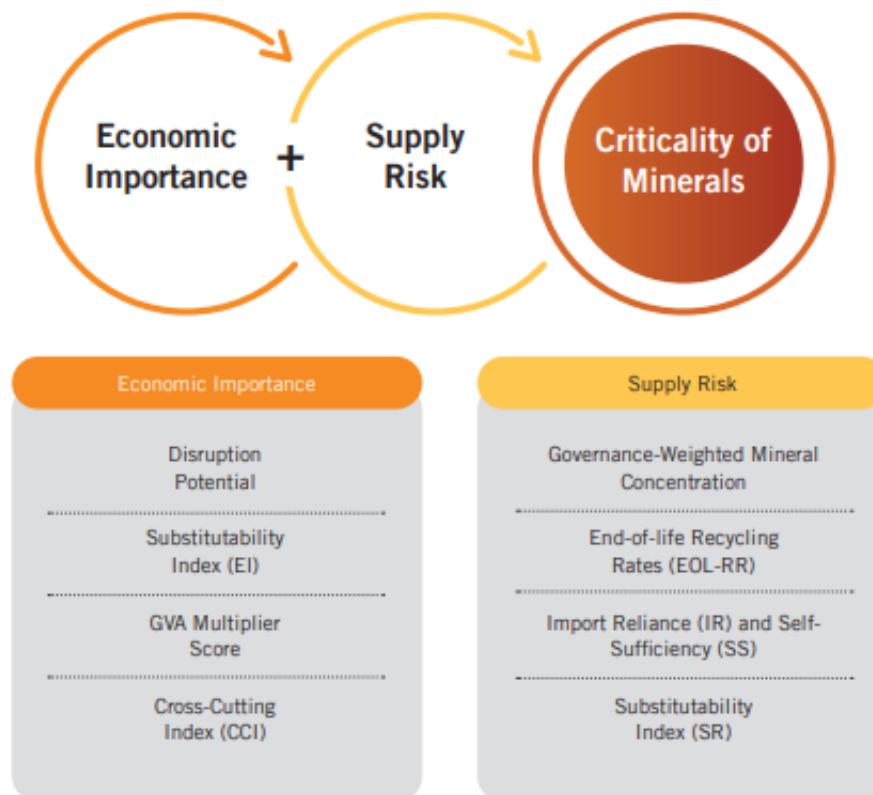
लायिम और अन्य महत्त्वपूर्ण खनजिं के आयात एवं शोधन पर भारत की भारी नियन्त्रण गंभीर चुनौतियाँ पेश करती हैं। भारत महत्त्वपूर्ण खनजिं के प्रति अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर अपनी आर्थिक प्रगति को प्रयावरण संरक्षण के साथ बेहतर ढंग से संरेखित कर सकता है और सतत ऊर्जार्थ इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी की ओर वैश्वकि संक्रमण के बीच अपनी स्थितिको सुदृढ़ कर सकता है।

महत्त्वपूर्ण खनजि (Critical Minerals) क्या हैं?

- परिचय:** महत्त्वपूर्ण खनजि वे खनजिं हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक होते हैं।
 - इन खनजिं की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों तक ही इनकी उपलब्धता, निषिक्रष्ण या प्रसंस्करण की सीमितता के कारण आपूर्ति शून्खला में भेदभाव और व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
- मुख्य वर्षीयताएँ:**
 - आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिये आवश्यक:** महत्त्वपूर्ण खनजि स्वच्छ ऊर्जा (**सौर पैनल, पवन ट्रबाइन, इलेक्ट्रिक वाहन**) से लेकर इलेक्ट्रोनिक्स, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक विभिन्न प्रौद्योगिकीयों में अपरहित घटक होते हैं।
 - भू-राजनीतिक महत्त्व:** उनकी आपूर्ति प्रायः कुछ ही देशों में केंद्रित है, जिससे वे आपूर्ति शून्खला व्यवधानों और मूल्य में उत्तार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
 - प्रयावरणीय प्रभाव:** यदि इन खनजिं के निषिक्रष्ण और प्रसंस्करण का प्रबंधन ज़मिनेदारी से नहीं किया गया तो इसके महत्त्वपूर्ण प्रयावरणीय परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनजि:** खान मंत्रालय ने 30 ऐसे खनजिं की पहचान की है जो भारत के प्रौद्योगिकीय और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
 - अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और अनुभवजन्य विशेषज्ञता के माध्यम से इन खनजिं का आकलन एवं नियन्त्रण करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था।
 - समिति ने महत्त्वपूर्ण खनजिं के लिये उत्कृष्टता केंद्र की (Centre of Excellence) स्थापना की सफारियों की ताकि महत्त्वपूर्ण खनजिं की सूची को समय-समय पर अद्यतन और रणनीतिक बनाया जा सके तथा प्रभावी मूल्य शून्खला विकासित की जा सकें।
- भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनजि:** एंटीमनी, बेरलियम, बस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जरमेनियम, ग्रेफाइट, हैफननियम, इंडियम,

लथियम, मोलबिडेनम, नायोबियम, नक्किल, प्लैटनिम समूह के तत्व (PGE), फॉस्फोरस, पोटाश, दुर्लभ मृदा तत्व (REE)), रेनयिम, सलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टनि, टाइटेनयिम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़रिकोनयिम, सेलेनयिम, कैडमयिम।

II



इन खनजिं को महत्वपूरण क्यों माना जाता है?

- ऊर्जा संकरण और इलेक्ट्रिक मोबालिटी:** महत्वपूरण खनजि, वशिषकर लथियम, स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबालिटी की ओर भारत के संकरण के लिये अत्यंत महत्वपूरण हैं।
 - देश का लथियम आयात वर्तित वर्ष 2022 में 13,673.15 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्तित वर्ष 2023 में 23,171 करोड़ रुपए हो गया, जो इसकी बढ़ती मांग को रखांकति करता है।
 - भारत ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन वज़िन (EV Vision) के तहत वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन पैठ का लक्ष्य रखा है, जिसके लिये इन खनजिं तक सुरक्षित पहुँच का होना अत्यंत महत्वपूरण है।
 - बजट 2024 में महत्वपूरण खनजिं पर सीमा शुल्क में छूट के प्रस्ताव से यह प्रदर्शनि होता है कि सरकार EVs अंगीकरण में तेज़ी लाने और उत्पादन लागत को कम करने में इनके महत्व को चहिनति करती है।
- अंतरकिष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी:** भारत का महत्वाकांक्षी अंतरकिष कार्यक्रम, जिसमें '[गगनयान](#)' जैसे मशिन शामिल हैं, महत्वपूरण खनजिं पर अत्यधिक निर्भर करता है।
 - भारतीय अंतरकिष अनुसंधान संगठन (ISRO)** अपनी क्षमताओं का वसितार कर रहा है, जहाँ वह वर्ष 2035 तक एक अंतरकिष स्टेशन स्थापति करने की योजना रखता है।
 - दुर्लभ मृदा तत्व और अन्य महत्वपूरण खनजि उपग्रहों एवं अंतरकिष यानों में प्रयुक्त उच्च-प्रदर्शन चुंबकों, वशिष मशिरधातुओं और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के वनिरिमाण के लिये आवश्यक हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना:** महत्वपूरण खनजि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिये अत्यंत महत्वपूरण हैं, जहाँ [वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा](#) क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
 - इंडियम, गैलियम और टेल्यूरियम जैसे खनजि सोलर पीवी (solar PV) प्रौद्योगिकी के लिये आवश्यक हैं, जबकि दुर्लभ मृदा तत्व पवन टर्बाइनों के लिये महत्वपूरण हैं।
 - इन संसाधनों को सुरक्षित करना न केवल जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक है, बल्कि भारत सुरक्षा सुनिश्चिति करने और जीवाशम ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने में भी इनकी महत्वपूरण भूमिका होगी, जिसका भारत के व्यापार संतुलन और ऊर्जा स्वायत्तता पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और दूरसंचार:** चूँकि भारत की [डिजिटल अर्थव्यवस्था](#) के वर्ष 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अवसंरचना में महत्वपूरण खनजिं की मांग में वृद्धि होगी।
 - डिजिटल इंडिया और 5G नेटवर्क** की शुरुआत जैसी पहलों की सफलता काफी हद तक गैलियम, इंडियम और टैंटलम जैसे खनजिं पर निर्भर करती है।

- ‘सलिकॉन हार्ट’ की महत्त्वपूर्ण खनजिं पर नरिभरता: आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मस्तिष्क होने की स्थिति रखने वाले सेमीकंडक्टर्स महत्त्वपूर्ण खनजिं पर अत्यधिक नरिभर होते हैं।
 - **सलिकॉन हार्ट (Silicon Heart)** से तात्पर्य है सलिकॉन आधारित उपकरण (जैसे सेमीकंडक्टर्स, चपिस आदि), जो महत्त्वपूर्ण खनजिं पर नरिभर होते हैं।
 - सलिकॉन, जर्मनियम और गैलियम जैसे तत्व सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिये मूलभूत हैं।
 - भारत के सेमीकंडक्टर मशिन का उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर वनिरिमाण को बढ़ावा देना है, जो प्रौद्योगिकीय आत्मनिरिभरता प्राप्त करने और आयात नरिभरता को कम करने में इन खनजिं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
 - इसके अलावा, राष्ट्रीय क्यांटम मशिन और इंडिया-एआई (IndiaAI) मशिन भी सलिकॉन पर अत्यधिक नरिभर हैं।
- भू-राजनीतिक प्रभाव: महत्त्वपूर्ण खनजिं की सुरक्षा भारत की भू-राजनीतिक स्थिति और सौदेबाज़ी की शक्ति को बढ़ाएगी।
 - **खनजि सुरक्षा साझेदारी (Minerals Security Partnership- MSP)** जैसे वैश्वकि मंचों में देश की भागीदारी और हाल ही में भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्त्वपूर्ण खनजि निविश साझेदारी (India-Australia Critical Minerals Investment Partnership) जैसे द्विपक्षीय समझौते, इसके अग्रसक्राय दृष्टिकोण को परिवर्क्षित करते हैं।
 - ये पहले न केवल आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करती हैं, बल्कि भारत को वैश्वकि खनजि कूटनीति में एक प्रमुख खलिझी के रूप में स्थापित करती हैं।

भारत के लिये महत्त्वपूर्ण खनजिं से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भारत की आयात नरिभरता: महत्त्वपूर्ण खनजिं के लिये आयात पर भारत की भारी नरिभरता गंभीर आरथिक एवं रणनीतिक जोखमि उत्पन्न करती है।
 - इन संसाधनों के भू-राजनीतिक संकेंद्रण को देखते हुए यह नरिभरता विशेष रूप से चिताजनक है।
 - इन खनजिं के प्रसंस्करण में चीन का प्रभुत्व (लिथियम का 67%, कोबाल्ट का 73%, ग्रेफाइट का 70% और मैग्नीज का 95%) भारत की आपूर्ति शृंखला सुरक्षा के लिये गंभीर जोखमि पैदा करता है।
 - यह एकाधिकारवादी नियंत्रण भारत को आपूर्ति विवरधान, मूल्य अस्थरिता और संभावित भू-राजनीतिक लाभ के प्रति संवेदनशील बना देता है।
- अन्वेषण की समस्या: हाल के प्रयासों के बावजूद, महत्त्वपूर्ण खनजिं के लिये भारत का घरेलू अन्वेषण अभी भी प्रारंभिक अवस्था में ही है।
 - देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में संभावित भंडारों की पहचान की है, लेकिन बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक निषिकरण अभी तक संभव नहीं हो पाया है।
 - **जम्मू और कश्मीर में 5.9 मलियन टन लिथियम भंडार** की खोज आशाजनक है, लेकिन इसके विकास के लिये अभी महत्त्वपूर्ण निविश और समय की आवश्यकता होगी।
 - अन्वेषण की धीमी गतिजितलि भूवैज्ञान, उन्नत अन्वेषण प्रौद्योगिकियों की कमी तथा नियामक बाधाओं जैसी चुनौतियों के कारण और भी गंभीर हो गई है।
- मूल्य शृंखला में लुप्त कड़ियाँ: महत्त्वपूर्ण खनजिं के प्रसंस्करण और शोधन में भारत की सीमित क्षमता एक महत्त्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करती है।
 - देश को कच्चा माल प्राप्त हो भी जाए तो घरेलू प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण परिष्कृत उत्पादों के लिये उसे अन्द्रेशों (मुख्यतः चीन) पर नरिभर रहना पड़ेगा।
 - मूल्य शृंखला में यह अंतराल न केवल लागत बढ़ाता है, बल्कि इन संसाधनों की पूर्ण आरथिक क्षमता का दोहन कर सकने की भारत की क्षमता को सीमित करता है।
 - सुदृढ़ घरेलू प्रसंस्करण उद्योग का अभाव बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स वनिरिमाण जैसे डाउनस्ट्रीम वनिरिमाण क्षेत्रों के विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है, जबकि **‘मेक इन इंडिया’** और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मशिन योजना जैसी पहलों के लिये उनका विकास अत्यंत आवश्यक है।
- निषिकरण और प्रारसिथितिकी में संतुलन: महत्त्वपूर्ण खनजिं के निषिकरण और प्रसंस्करण से प्रायः गंभीर प्रयावरणीय लागत भी जुड़ी होती है।
 - खनन कार्यों से प्रयावास वनिश, जल प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है।
 - भारत पहले से ही प्रयावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है और उसे अपनी महत्त्वपूर्ण खनजि आवश्यकताओं को पारसिथितिकी संरक्षण के साथ संतुलित करने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
 - उदाहरण के लिये, लद्दाख के पारसिथितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में संभावित लिथियम खनन से जल की कमी और जैव विविधिता की हानि के बारे में चिंता पैदा होती है।
 - उल्लेखनीय है कि एक औसत सलिकॉन चपि वनिरिमाण संयंत्र प्रतिदिन 10 मलियन गैलन अतिशुद्ध जल का उपयोग कर सकता है।
 - इन खनजिं की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए प्रयावरण की दृष्टि से संवहनीय खनन पद्धतियों का विकास करना नीतिनिरिमाताओं और उद्योग दोनों के लिये एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है।
- मूल्य अस्थरिता - एक दोधारी तलवार: महत्त्वपूर्ण खनजि बाजार अत्यधिक मूल्य उत्तार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रखता है, जिससे भारत की वनिरिमाण लागत और प्रतिस्परद्धात्मकता प्रभावित होती है।
 - हाल के वर्षों में लिथियम की कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन उत्पादन अरथव्यवस्था प्रभावित हुई है।
 - मूल्य अस्थरिता निविशकों और इन खनजिं पर नरिभर उद्योगों के लिये अनश्चितिता पैदा करती है, जिससे दीर्घकालिक योजना-निरिमाण और निविश में बाधा उत्पन्न होती है।

भारत के महत्त्वपूर्ण खनजिं के लिये शुद्ध आयात नरिभरता (2020)

महत्त्वपूर्ण खनजि	प्रमुख आयात स्रोत (2020)
लथियम	चीन, रूस, चीन, आयरलैंड, बेल्जियम
कोबाल्ट	चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड, अमेरिका, जापान
नक्किल	स्वीडन, चीन, इंडोनेशिया, जापान, फलीपीस
वैनेडियम	कृष्णात, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, थाईलैंड
नयोबियम	ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया
जर्मेनियम	चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका
रेनियम	रूस, ब्राटिन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन
बेरलियम	रूस, ब्राटिन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, चीन
टैटालम	ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अमेरिका
जरिकोनियम	ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अमेरिका
ग्रेफाइट (प्राकृतिक)	चीन, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, विहितनाम, तंजानिया
मैंगनीज	दक्षिण अफ्रीका, गैर्भॉन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन
क्रोमियम	दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, ओमान, स्विट्जरलैंड, तुर्की
सलिकिंग	चीन, मलेशिया, नार्वे, भूटान, नीदरलैंड
स्ट्रोंटियम	चीन, अमेरिका, रूस, एस्टोनिया, स्लोवेनिया

नोट:

खान और खनजि (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 भारत में महत्त्वपूर्ण खनजियों की खोज और खनन को बढ़ाने के लिये प्रमुख सुधार प्रस्तुत करता है।

- परमाणु खनजियों से छह खनजियों को हटाया गया: नजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और उत्पादन बढ़ाने के लिये लथियम-युक्त टाइटेनियम-युक्त, बेरलियम-युक्त, नयोबियम-युक्त, टैटालम-युक्त और जरिकोनियम-युक्त खनजियों को परमाणु खनजियों की सूची से हटा दिया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा नीलामी: केंद्र सरकार विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण खनजियों के लिये खनजि रियायतों की नीलामी करेगी, जिससे राज्य सरकारों को राजस्व का लाभ प्राप्त होगा।
- अन्वेषण लाइसेंस: गहराइ में अवस्थिति और महत्त्वपूर्ण खनजियों के लिये नए अन्वेषण लाइसेंस पेश किये जाएंगे, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी नविश और जूनियर खनन कंपनियों को आकर्षित करना तथा अन्वेषण एवं उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है।

भारत अपनी महत्त्वपूर्ण खनजि आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिये कौन-से उपाय कर सकता है?

- महत्त्वपूर्ण खनजि संबंधी कूटनीति:** संसाधन सुरक्षा के लिये वैश्वकि गठबंधन (Global Alliances for Resource Security) का निर्माण करना। भारत को महत्त्वपूर्ण खनजि संबंधी कूटनीतिक प्रयासों को तेज़ करना चाहिये और संसाधन संपन्न देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करनी चाहिये। इसमें शामिल हो सकते हैं:
 - सरकार के स्तर पर (Government-to-Government – G2G)** और भी सौदों को संपन्न करने के लिये वार्ता के लिये खनजि विदेश इंडिया लमिटेड के अधिदिश का विस्तार किया जाए।
 - वैश्वकि उझानों और अवसरों पर नज़र रखने के लिये एक महत्त्वपूर्ण खनजि खुफिया इकाई (**Critical Minerals Intelligence Unit**) का गठन किया जाए।
 - खनजियों तक अधिमान्य पहुँच सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञता, अवसंरचना विकास या अन्य प्रोत्साहनों (incentives) की पेशकश की जाए।
- चक्रीय खनजि अर्थव्यवस्था (Circular Mineral Economy):** नमिनलियित उपायों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण खनजियों के लिये एक सुदृढ़ चक्रीय अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए:
 - बहुमूल्य खनजियों की पुनरप्राप्ति के लिये उन्नत ई-अपशिष्ट पुनरचक्रण प्रौद्योगिकियों को करियान्वति करना।
 - ऐसे EOL उत्पादों (**end-of-life products**) का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना जिनमें महत्त्वपूर्ण खनजि उपस्थिति हों।
 - भारत प्रमुख शहरों में विशेष पुनरचक्रण क्षेत्र स्थापित कर सकता है, जोई-अपशिष्ट से महत्त्वपूर्ण खनजियों को निकालने के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित हों। ये त्यक्त इलेक्ट्रॉनिक्स से दुर्लभ मृदा तत्वों के 50-60% तक को पुनः प्राप्त कर सकेंगे।
- खनजि तकनीक में प्रगतिकरना:** नमिनलियित उपायों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण खनजि के नष्टिकरण और प्रसंस्करण में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाए:
 - सफल रहे अंतरक्रिय और परमाणु ऊरजा कार्यक्रमों की तरह 'महत्त्वपूर्ण खनजि प्रौद्योगिकी मिशन' (Critical Minerals Technology Mission) की स्थापना करना।
 - महत्त्वपूर्ण खनजि प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास नविश के लिये कर प्रोत्साहन (**tax incentives**) की पेशकश करना।
 - अत्याधुनिक नष्टिकरण और प्रसंस्करण तकनीकों के विकास पर केंद्रित उदयोग-अकादमिक साझेदारियों का निर्माण करना।
 - खनजि प्रसंस्करण में वैश्वकि अग्रणी देशों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को सुविधाजनक बनाना।

- **जयो-मैपिंग क्रांति (GeoMapping Revolution):** नमिनलखिति उपायों के साथ घरेलू खनजि अन्वेषण प्रयासों को तीव्र एवं आधुनिक बनाया जाएः
 - AI और मशीन लर्निंग सहित उन्नत भूवैज्ञानिक मानचित्रण तकनीकों का उपयोग करना।
 - संभावति खनजि समृद्ध क्षेत्रों का व्यापक हवाई और उपग्रह सर्वेक्षण करना।
 - जोखिम-साझाकरण तंत्र के माध्यम से अन्वेषण में नजिकी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
 - अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
- **हरति खनन पहल (Green Mining Initiative):** नमिनलखिति उपायों के साथ भारत के अद्वतीय पारस्थितिक संदर्भ के अनुरूप खनन पद्धतियों का विकास किया जाएः
 - महत्वपूर्ण खनजिओं के खनन के लिये सख्त प्रयावरण मानकों को लागू करना।
 - खनन स्थलों के लिये एक व्यापक भूमिपुनर्वास कार्यक्रम विकसित करना।
 - खनन कारयों के लिये संवहनीयता रेटिंग प्रणाली का निर्माण करना।
 - लद्दाख से शुष्क क्षेत्रों के लिये उपयुक्त जल-संरक्षक लथियम निषिकरण विधियों के विकास का समर्थन करने के लिये 'हरति खनन नवाचार कोष' (Green Mining Innovation Fund) की स्थापना करना।
- **महत्वपूर्ण खनजिओं के लिये 'स्कलि इंडिया':** नमिनलखिति उपायों के साथ महत्वपूर्ण खनजि क्षेत्र में कौशल अंतराल को दूर किया जाएः
 - तकनीकी संस्थानों में महत्वपूर्ण खनजि भूवैज्ञान, निषिकरण और प्रसंस्करण में विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना।
 - खनजि समृद्ध क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना।
 - महत्वपूर्ण खनजि संबंधी पेशेवरों के लिये एक राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करना।
- **खनजि प्रसंस्करण पारक:** नमिनलखिति उपायों के साथ घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिये समरपति खनजि प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापति किया जाएँ:
 - इन क्षेत्रों में कर प्रोत्साहन और सरलीकृत वनियामक प्रक्रियाएँ प्रदान करना।
 - बजिली, जल और लॉजिस्टिक्स सहायता सहित विशेष-स्तरीय अवसंरचना सुनिश्चित करना।
 - तालमेल के निर्माण के लिये संबंधित उद्योगों की सह-अवस्थिति को प्रोत्साहित करना।
- **खनजि-बाजार गलियारे (Mineral-to-Market Corridors):** नमिनलखिति उपायों के साथ खनजि समृद्ध क्षेत्रों को प्रसंस्करण केंद्रों और बाजारों से जोड़ने के लिये समरपति अवसंरचना गलियारे बनाए जाएँ:
 - रशिल-टाइम ट्रैकिंग क्षमताओं के साथ स्मार्ट लॉजिस्टिक्स हब स्थापति करना।
 - इन गलियारों को ऊर्जा प्रदान करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करना।
 - IoT और समार्ट माइनिंग अनुप्रयोगों के लिये डेटा कनेक्टिविटी अवसंरचना को शामिल करना।
 - उदाहरण के लिये, लद्दाख से गुजरात के वनिरिमान केंद्रों तक, सौर ऊर्जा संचालित लॉजिस्टिक्स केंद्र और संपूर्ण क्षेत्र में 5G कनेक्टिविटी के साथ, 'लथियम कॉरिडोर' का विकास किया जाए।

अभ्यास प्रश्न: भारत के आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण खनजिओं के महत्व पर चर्चा कीजिये। उनकी आपूरत शृंखला की भेद्यताओं से जुड़े संभावित जोखिमों का मूल्यांकन कीजिये और इन जोखिमों को कम करने के लिये रणनीतियाँ प्रस्तावित कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में गौण खनजि के प्रबंधन के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस देश में विद्यमान विधिके अनुसार रेत एक 'गौण खनजि' है।
2. गौण खनजिओं के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्तिराज्य सरकारों के पास है, कनिन्तु गौण खनजिओं को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं।
3. गौण खनजिओं के अवैध खनन को रोकने के लिये नियम बनाने की शक्तिराज्य सरकारों के पास है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 3
 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत में ज़िला खनजि फाउंडेशन का/के क्या उद्देश्य है/हैं? (2016)

1. खनजि समृद्ध ज़िलों में खनजि अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना
2. खनन कारयों से प्रभावित व्यक्तियों के हतों की रक्षा करना।

3. राज्य सरकारों को खननि अन्वेषण के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न:

प्रश्न : गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बहुत कम प्रतशित योगदान है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) (2021)

प्रश्न. "प्रतकूल प्रयावरणीय प्रभाव के बावजूद विकास के लिये कोयला खनन अभी भी अपरहित है"। चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-path-to-securing-critical-minerals>

